निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप हों। चीनी मिलों से लेवी चीनी या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नामितियों द्वारा या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी स्टॉकों को, उन्हें स्वीकार करने से पूर्व, जांच करने की अनुमति है और उन्हें स्टॉक के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने पर उसे अस्वीकार करने का अधिकार है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं के वितरण में कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर दुकान के स्तर पर उपभोक्ताओं की सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

Coal Production in Andhra Pradesh

1326. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the expected production of coal from Andhra Pradesh in 1995-96;

(b) whether any shortfall is expected; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the expected coal production from Singareni Collieries Co. Limited (SCCL) situated in Andhra Pradesh. The target of coal production set for the SCCL for the year 1995-96 is 28.00 million tonnes, against which the company has achieved a production of 13.67 million tonnes (provisional) during the period April—November, 1995. On account of sporadic strikes the company had suffered some production loss during the year so far. The extent of shortfall in achieving target will be known only at the end of the financial year.

अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने हेतु उठाए गए कदम

1327. **श्री सतीश अग्रवाल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक वस्तुओं को नियंत्रित करने/कम करने/न्यूनतम करने हेतु क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने खुला सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में कांट-छांट की है ताकि मुद्रा बाजार में चालू अस्थिरता की स्थिति को सुधारा जा सके; और

(ग) क्या सरकार ने उन सटोरियों और चालबाजों का पता लगाया है जिन्होंने मुद्रा बाजार में यह सन्त्रास पैदा किया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखते हुए समग्र आर्थिक तथ्यों पर विचार करने के बाद किए जाते हैं। वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं का आयात पहले ही प्रतिबंधित है। भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने तथा अटकलों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपाय किए हैं।

Stock of Sugar in the Country

1328. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the details of quantity of sugar stock in the country at present;

(b) the reasons why full quota of sugar has not been supplied to the fair price shops from time to time since January, 1995; and

(c) the steps taken to ensure that Fair Price Shopkeepers do not indulge in blackmarketing on account of shortage in supply?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The sugar season is reckoned from October to September. Accordingly, the stocks of indigenous sugar as on 01.10.1995 were 55.57 lakh